ई-संदेश

उत्तर प्रदेश

11 जुलाई, 2018 • वर्ष 1, अंक 25

सात दिन – सात पृष्ठ

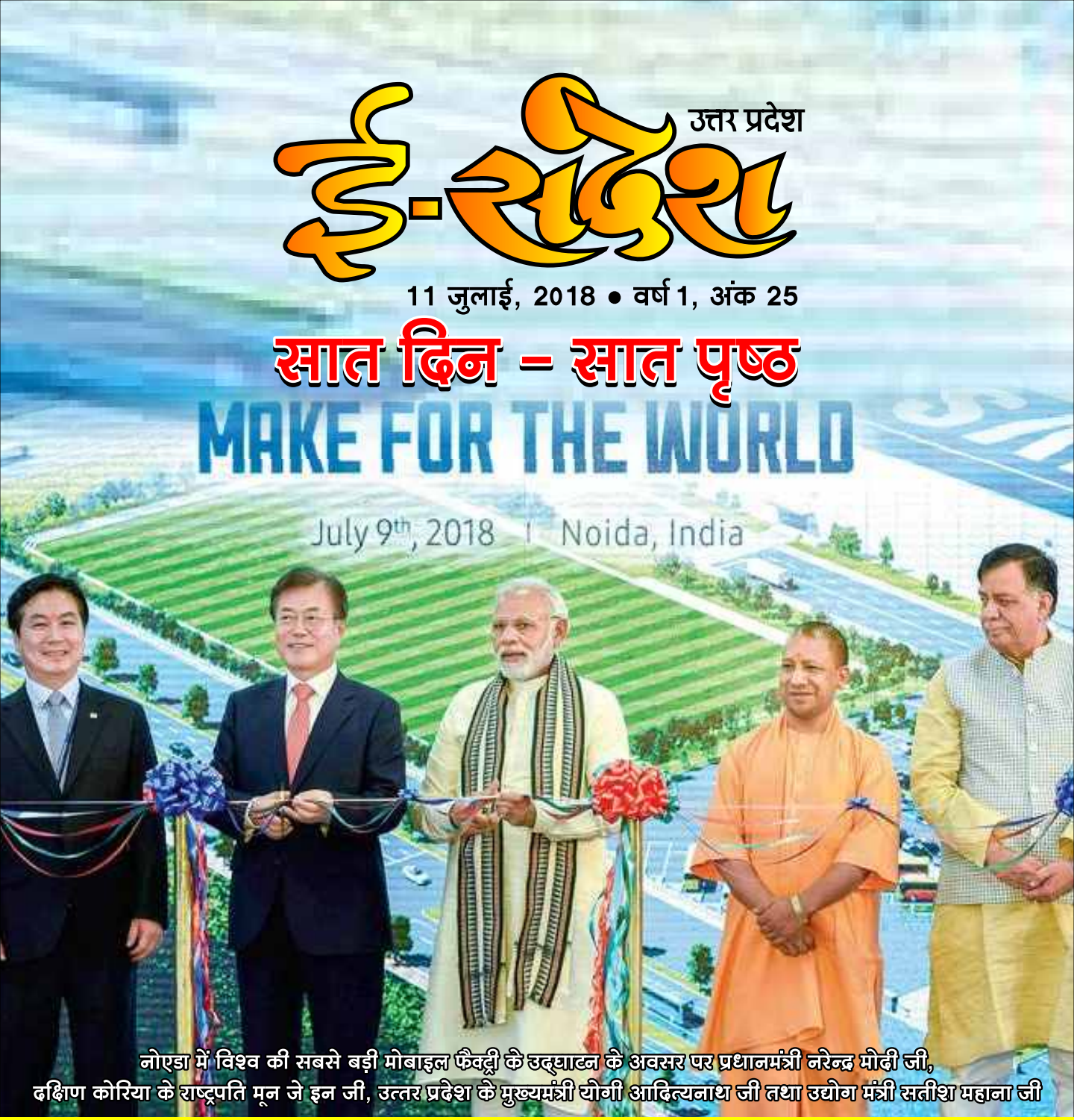

नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उद्योग मंत्री सतीश महाना जी

- प्रदेश में इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगी निजी कंपनियां
- प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु मुफ्त जमीन देगी सरकार
- नोएडा में स्थापित हुई विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री
- पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार लगाएगी नौ करोड़ पौधे
- 2.35 करोड़ किसानों को डेढ़ गुना तक ज्यादा मिलेगी कीमत
- 27438 करोड़ लागत से लखनऊ में बनेंगे तीन फ्लाई ओवर

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

प्रदेश में इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगी निजी कंपनियां

भूमि क्रय और लोन पर ब्याज में मिलेगी आकर्षक छूट

प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मुहैया करवाने के लिए कैबिनेट ने प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के प्रोत्साहन की योजना को मंजूरी दे दी है।

मिलेंगी कई तरह की रियायतें

पहली बार प्रदेश में सरकारी निगमों के साथ–साथ निजी कंपनियां भी इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगी। नई निजी औद्योगिक पार्कों के प्रोत्साहन योजना में राज्य सरकार ने नई तरह की रियायतों का प्रावधान किया है।

एक्सप्रेस–वे के किनारे डेवलप होंगे इंडस्ट्रियल पार्क

इन इंडस्ट्रियल पार्क को एक्सप्रेस–वे के किनारे डिवेलप किया जा सकता है। मौजूदा समय में प्रदेश में दो एक्सप्रेस–वे हैं जबकि तीसरे सबसे लंबे एक्सप्रेस–वे पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का काम इसी महीने शुरू होगा। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे का निर्माण भी राज्य सरकार करवा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से इलाहाबाद और गोरखपुर के लिए भी लिंक एक्सप्रेस–वे निकल रहा है। इसके अलावा नोएडा और यमुना एक्सप्रेस–वे को आईटी ऐंड इलेक्ट्रानिक्स हब के रूप में डिवेलप करेगी। इसमें यह पॉलिसी काफी सहायक साबित होगी।

बड़े पैमाने पर मिलेंगी नौकरियां

निजी पार्कों में इंडस्ट्री डिवेलप होने से बढ़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इससे खासतौर पर आईटी और इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर की कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु मुफ्त जमीन देगी सरकार

ईडब्ल्यूएस व एलआईजी श्रेणी के मकान बनाना हुआ आसान

शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई– शहरी) के तहत बनने वाले दुर्बल आय (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के मकानों के लिए सरकार मुफ्त में जमीन देगी।

कम कीमत में बनेंगे मकान

शहरों में जमीनों की उपलब्धता कम और कीमत अधिक होने से पीएमएवाई के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के मकान बनाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता से बनने वाले किफायती आवास घटक के अंतर्गत योजना के लिए मुफ्त में जमीन देने का फैसला किया है। शहरों की नजूल, अर्बन सीलिंग की सरप्लस भूमि, ग्राम समाज, नगर निगम, लोक निर्माण, सिंचाई, विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद समेत अन्य सरकारी विभागों की खाली पड़ी भूमि निःशुल्क दी जाएगी।

10 मंजिला बनेंगे मकान

शहरी क्षेत्र में अब चार के स्थान पर 10 मंजिला अपार्टमेन्ट बनाए जाएंगे। अभी भूतल के अलावा तीन मंजिला तक अपार्टमेन्ट बनाने की लागत सरकार द्वारा तय लागत से अधिक है। इसलिए निजी क्षेत्र के बिल्डर इसमें रूचि नहीं ले रहे थे। इस दिक्कत को देखते हुए सरकार ने अब भूतल के अलावा 9 मंजिला तक बनाने का फैसला किया है।

सीएम की पहल से नोएडा में स्थापित हुई विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री

मेक इन इण्डिया को बढ़ाने में मिलेगी मदद

विगत 7 जून, 2017 को सैमसंग ने उत्तर प्रदेश सरकार की मेगा पॉलिसी के तहत 4,915 करोड़ रुपए के निवेश के साथ नोएडा प्लाण्ट की क्षमता बढ़ाने की घोषणा की थी और यह सपना अब पूरा हुआ है। भारत में मेक इन इण्डिया कार्यक्रम को बढ़ाने में कोरिया का महत्वपूर्ण योगदान है। इस कम्पनी की निर्माण इकाई के आरम्भ होने से हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

यह उद्गार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जई इन जी के साथ गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में संयुक्त रूप से सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स की नई मोबाइल फोन निर्माण इकाई का उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किए।

इस नई फैक्टरी के साथ, सैमसंग नोएडा में अपनी मोबाइल फोन निर्माण की वर्तमान क्षमता को सालाना 6.8 करोड़ फोन यूनिट से 12 करोड़ यूनिट तक बढ़ाकर दोगुना करने का काम करेगा। कंपनी द्वारा भारत में मोबाइल फोन का निर्माण वर्ष 2007 से किया जा रहा है और यह अकेला ऐसा ब्रैण्ड है, जो पूरी तरह से मेड इन इण्डिया है। सैमसंग अपनी स्थापना से ही प्रिण्टेड सर्किट बोर्ड को बढ़ावा दे रहा है और यह भारत सरकार के फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के लक्ष्यों के साथ जुड़ा है।

नोएडा फैक्टरी, जिसे 1996 में स्थापित किया गया था, भारत में स्थापित की गई पहली ग्लोबल इलेक्ट्रानिक निर्माण सुविधाओं में से एक है। 1,29,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह नया और बड़ा प्लाण्ट, सैमसंग को देशभर में अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने और भारत को दुनिया का एक्सपोर्ट हब बनाने के सपने को साकार करने में मदद करेगा।

भारत के सहयोग से विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल कम्पनी की निर्माण इकाई का नोएडा में शुभारम्भ हुआ है। दोनों देश आपसी सहयोग से आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के पुराने आपसी सम्बन्ध हैं। आज भारत और दक्षिण कोरिया विश्व में अच्छे दोस्त हैं। यह दोस्ती आगे भी इसी प्रकार कायम रहेगी और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होगी।

हजारों नौजवानों को मिलेगा रोजगार

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि दक्षिण कोरिया द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एम.ओ.यू. साइन के उपरान्त एक वर्ष के भीतर सैमसंग द्वारा यह मोबाइल कम्पनी स्थापित की जाएगी। इतने कम समय में निर्माण इकाई की स्थापना अपने आप मे एक गौरव का विषय है। इसकी स्थापना में प्रदेश सरकार की अहम भूमिका रही है। प्रदेश सरकार द्वारा 22 किलोमीटर विद्युत लाइन तैयार कराते हुए 50 मेगावॉट का कनेक्शन सैमसंग को प्रदान कराया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा आगे भी इसी प्रकार सहयोग प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी सैमसंग मोबाइल कम्पनी की निर्माण इकाई का शुभारम्भ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसमें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जी का सहयोग उल्लेखनीय है। इससे प्रदेश में जहां एक ओर हजारों की संख्या में जनसामान्य को रोजगार प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में मेक इन इण्डिया कार्यक्रम तेजी से प्रगति करेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम एवं रोजगार सृजन के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। ■

120 खादी कामगारों को मिलगा आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण

खादी को जन सामान्य में लोकप्रिय बनाने एवं आधुनिक बाजार मांग के अनुरूप उत्पादन के लिए खादी कामगारों को आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेंगे। इस वर्ष 120 खादी कामगारों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

खादी में अधिक से अधिक स्वरोजगार सृजन के उद्देश्य से सोलर चर्खा प्रशिक्षण एवं वितरण योजना प्रस्तावित है। इसके प्रथम चरण में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के 400 चयनित लाभार्थियों को सोलर चर्खा संचालन प्रशिक्षण प्रदान करते हुए खादी संस्थाओं के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने तथा जन सामान्य में खादी को लोकप्रिय तथा सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से आन लाइन मार्केटिंग पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश की 10 इकाईयों के उत्पाद आन लाइन बिक्री हेतु अमेजन के प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं और लगभग 40 अन्य उत्पादों को जल्द ही आनलाइन लाने की तैयारी की जा रही है।

पारम्परिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण हेतु तत्पर है सरकार

प्रदेश सरकार द्वारा पारम्परिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण तथा उसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के साथ–साथ उनकी आय में वृद्धि के लिए **'एक जनपद, एक उत्पाद'** योजना संचालित की जा रही है। सरकार परम्परागत उत्पादों के निर्यात, प्रोत्साहन सहित स्थानीय उद्यमों में निवेश प्रोत्साहन हेतु भी निरन्तर प्रयत्नशील है तथा इसके लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की शुरुआत के लिए **'निवेश मित्र पोर्टल'** प्रारम्भ किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुरादाबाद में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' योजना की समीक्षा बैठक के दौरान यह उद्गार व्यक्त किए।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के विशिष्ट उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राण्डिंग के प्राथमिक उद्देश्य के साथ–साथ रोजगार सृजन, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी सामर्थ्य के विकास, तकनीकी उन्नयन, कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के कौशल विकास हेतु 'ओ.डी.ओ.पी. योजना' क्रियान्वित की जा रही है।

ओ.डी.ओ.पी. योजना के अंतर्गत मुरादाबाद की विश्व विख्यात ब्रास वेयर इण्डस्ट्री अथवा मेटल हैण्डीक्राफ्ट्स पीतल उद्योग का चयन किया गया है। जनपदवार उपलब्ध संसाधनों जैसे रॉ–मैटेरियल, डिजाइन, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, डिस्प्ले एवं मार्केटिंग से सम्बन्धित सुविधाओं की मैपिंग करते हुए स्वाट एवं गैप एनालिसिस के आधार पर आवश्यक ईको सिस्टम तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है। इसके लिए बेस लाइन सर्वे एवं उपलब्ध सेल्फ डेवलप्ड उत्पाद समूहों का अध्ययन कर डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु परामर्शी संस्थाओं से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेण्ट के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा चुके हैं।

मेटल आर्ट वेयर उत्पादों के निर्माण से जुड़े लगभग 2.50 से 3 लाख लोगों को लाभ दिलाने की तैयारी

धातु शिल्प कार्यो के लिए मुरादाबाद जनपद को विश्वख्याति प्राप्त है। अतः धातु शिल्प कार्यो/उत्पादों को उत्कर्षता की सीमा तक पहुंचाने के लिए इस उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों एवं कारीगरों, वर्करों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। ■

प्रदेश के 2.35 करोड़ किसानों को डेढ़ गुना तक ज्यादा मिलेगी कीमत

कृषक हितैषी इस निर्णय का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा। कृषि को लाभकारी बनाने तथा किसानों की खुशहाली को बढ़ाने में केन्द्र सरकार का यह निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार एक कार्ययोजना बनाकर गम्भीरता से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। गत माह केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में घोषित किए गए चीनी उद्योग पैकेज के साथ–साथ खरीफ फसल के समर्थन मूल्य में वृद्धि सम्बन्धी इस निर्णय का प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

–योगी आदित्यनाथ

ये हैं खरीफ के नए एमएसपी

फसल	लागत	अब	पहले	वृद्धि (%)	नए फार्मूले से (%)
	प्रति क्विंटल/रुपये				
धान सामान्य	1166	1750	1550	12.9	50.09
धान ग्रेड-ए	---	1770	1590	11.3	51.80
अरहर	3432	5675	5450	4.12	65.36
मूंग	4650	6975	5575	25.1	50.00
उड़द	3438	5600	5400	3.7	62.89
रागी	1931	2897	1900	52.5	50.01
बाजरा	990	1950	1425	36.8	96.97
तिल	4166	6249	5300	18	50.00
काला तिल	3918	5877	4050	45.1	50.01
ज्वार हाइब्रिड	1619	2430	1700	42.9	50.09
ज्वार मालदंडी	---	2450	1725	42	51.33
कपास लंबा रेशा	--	5450	4320	26.1	58.75
कपास मध्यम रेशा	3433	5150	4020	28.1	50.01
सोयाबीन	2266	3399	3050	11.4	50.01
मूंगफली	3260	4849	4450	8.9	50.00
सूरजमुखी	3592	5388	4100	31.4	50.01

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2018–19 के खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का डेढ़ गुना या उससे अधिक बढ़ा दिया, अर्थात किसानों को अब अपनी फसल की लागत का डेढ़ गुना या इससे ज्यादा कीमत मिलेगी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 2 करोड़ 35 लाख किसानों को फायदा मिलेगा।

उत्पादकता बढ़ाने पर जोर

सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए यह एक सघन नीति पर काम कर रही है। इसका जोर उत्पादकता में वृद्धि करने, खेती की लागत को कम करने एवं बाजार ढांचा सहित पोस्ट–हार्वेस्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर है।

नये बाजार ढ़ांचे पर काम कर रही है सरकार

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक नये बाजार ढ़ांचे पर काम कर रही है कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। इसमें ग्रामीण कृषि बाजार (जीआरएएम) की स्थापना करना शामिल है ताकि फार्म गेट, ई–एनएएम के माध्यम से एपीएमसी पर प्रतिस्पर्धात्मक एवं पारदर्शी थोक बिक्री व्यापार तथा एक मजबूत और प्रो–कृषक निर्यात नीति के सानिध्य में 22,000 खुदरा बाजारों को बढ़ावा दिया जा सके। नई एमएसपी नीति जिसके तहत किसानों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ मार्जिन सुनिश्चित किया जा सके, सुधारों की श्रृंखला में एक दूसरा प्रगतिशील उपाय है।

बिचौलियों के शोषण से मुक्ति

प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक कार्य किया है। दुग्ध उत्पादन में हमारा प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश सरकार ने गेहूँ, दलहन, तिलहन की रिकार्ड खरीदारी की है और किसानों का एक–एक पैसा उनके खाते में ट्रांसफर किया है। बिचौलियों के शोषण से किसानों को मुक्त किया है। प्रदेश सरकार ने ज्वार, बाजरा तथा मूंग की भी खरीद की है। कम लागत में अधिक उत्पादन के गुर सिखाने के लिए गांव–गांव में किसान पाठशालायें आयोजित की जा रही हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण भी किया जा रहा है। सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने एवं तत्पश्चात उसके कल्याण में सुधार लाने के लिए वचनबद्ध है। ■

गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता

सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सभी गरीब पात्रों की बेटियों का कन्यादान एक पुण्य दान है। ऐसे आयोजनों से जुड़कर सभी लोगों को दहेज रहित शादी किए जाने के संकल्प लेना चाहिए जिससे रूढ़िवादी परम्परा को तोड़कर दहेज की कुरीति को मिटाई जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने सोनभद्र में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1001 जोड़ों की शादी में राज्य सरकार का शामिल होना और इसे सम्पन्न कराना एक सराहनीय कार्य है। सरकार गरीब/पात्र व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

लोक कल्याण के लिए सरकार सभी को बिना भेद–भाव किए लाभान्वित कर रही है। एक वर्ष में सरकार ने 8.85 लाख गरीब लोगों को आवास दिया। सोनभद्र जनपद में स्वीकृत 22 हजार प्रधानमंत्री आवास के सापेक्ष 20 हजार आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। प्रदेश सरकार सभी के भलाई के लिए कारगर कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि सोनभद्र जनपद के पात्र व्यक्तियों को हर हाल में सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश सरकार समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा कर रही है।

कानून का राज स्थापित करने में अभियोजन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका

किसी भी सामाजिक व्यवस्था में न्याय का स्थान सर्वोपरि होता है तथा सुशासन का पहला आधार कानून का राज है। न्याय व्यवस्था के सरल और सुदृढ़ होने से जनसामान्य का विश्वास कायम रहता है। प्रदेश में कानून का राज एवं सुशासन स्थापित करने में अभियोजन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुरादाबाद में प्रशिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि अभियोजन अधिकारी अपराधियों को दण्डित कराने एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करें।

संसदीय परम्पराओं को मजबूत करने में चन्द्रशेखर जी का योगदान अमूल्य : सीएम

पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी सही मायने में सच्चे समाजवादी नेता थे। चन्द्रशेखर जी ने हमेशा देश के गरीब, किसान, मजदूर एवं वंचित वर्गों के कल्याण तथा इन वर्गों के हितों में लगातार संसद में अपनी आवाज बुलन्द की। संसद में उनके योगदान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद भी चुना गया। देश में संसदीय परम्पराओं को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी की पुण्यतिथि पर 'राष्ट्रपुरुष चन्द्रशेखर–संसद में दो टूक भाग–दो' पुस्तक के विमोचन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि चन्द्रशेखर जी का मानना था कि भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में घरेलू और कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसके दृष्टिगत वर्तमान सरकार ने प्रदेश में 'एक जिला एक उत्पाद' योजना लागू की है। चन्द्रशेखर जी कॉमन सिविल कोड को जरूरी मानते थे। समाज और देश के हित में यह आवश्यक है कि सभी के लिए कानून समान हो। ■

पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार लगाएगी नौ करोड़ पौधे

प्रदेश में **'वन महोत्सव'** 1 से 31 जुलाई, 2018 तक चलाया जा रहा है। 'वन महोत्सव' के दौरान प्रदेश में पौधों का व्यापक रूप से रोपण किया जाएगा। सभी विभागों द्वारा समन्वित रूप से पर्यावरण संरक्षण के अभियान के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। यूकेलिप्टस के बजाय औषधीय गुण व धार्मिक महत्ता वाले पेड़ लगाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि नौ करोड़ पौधों को न सिर्फ लगाया जाएगा, बल्कि उनकी सुरक्षा भी होगी। एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाने का संकल्प ले। अगर वृक्षारोपण पर ध्यान नहीं दिया गया, तो जलवायु में भीषण संकट आएगा।

पीपल का वृक्ष पर्यावरण के लिए है सबसे उपयोगी

मुख्यमंत्री जी ने बाराबंकी में 'वन महोत्सव–2018' के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पीपल का वृक्ष पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसी प्रकार पाकड़, नीम और बरगद के पेड़ को भी लगाए जाने की आवश्यकता है। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों के आस–पास की भूमि पर वृक्ष लगाए जायेगे। देवा शरीफ में नदियों के आस–पास ग्राम समाज द्वारा वृक्ष लगवाए जाएंगे। वन प्राकृतिक नमी बनाए रखते हैं, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष रोपित किए जाएंगे।

प्लास्टिक मुक्त वातावरण है सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन तथा निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देकर संस्कृति और परम्परा के साथ आधुनिकता को जोड़कर विकास का कार्य कर रही है। गो–संरक्षण हेतु जनपदों में गौशाला खोली जाएंगी। नीलगाय से बचाव के लिए गाय के गोबर को खेत में फैला देने से नीलगाय नहीं आती। प्लास्टिक मुक्त वातावरण की व्यवस्था बनाई जाएगी। स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया जाएगी। महादेवा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रयास किए जायेंगे। प्रकृति और जीव–जन्तुओं के साथ समन्वय बनाकर रखने के लिए सभी को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। ■

पी.जी.आई. में जल्द बनेगा 500 बेड का द्वितीय फेज

457 करोड़ आएगी लागत

राज्य सरकार प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों को और बेहतर बनाने व मरीजों को उचित इलाज व आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है।

सरकार ने रोगियों की सुविधा के लिए पी.जी.आई. में 457 करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र ही 500 शैय्यायुक्त द्वितीय फेज के निर्माण का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त के.जी.एम.यू. में नयी बर्न यूनिट शीघ्र क्रियाशील होगी और लोहिया संस्थान में कैंसर रोगियों के लिए नवीन पैटसीटी व लीनियन एक्सलेटर शीघ्र क्रियाशील किये जायेंगे।

सभी संस्थान आपस में समन्वय बनाकर कार्य करेंगे, जिससे मरीजों को इलाज में किसी प्रकार की असुविधा न हो। पी.जी.आई. स्थित ट्रामा–II में आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए इसी माह में अवश्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा, जिससे मरीजों को इलाज की बेहतर व ससमय पर सुविधा मिल सके।

राम मनोहर लोहिया संस्थान में छात्रों के लिए हास्टल निर्माण, स्त्री रोग विभाग में लेबर रूम निर्माण, सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक एवं प्रशासनिक ब्लाक निर्माण आदि सभी कार्यों में तेजी लाकर शीघ्रता से पूरा किया जायेगा।

10 जुलाई 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे निर्माण में 1516 करोड़ की होगी बचत

पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे के निर्माण में राज्य सरकार 1516 करोड रूपये की बचत करेगी। 340 किलोमीटर लंबे लखनऊ से गाजीपुर तक बनने वाले इस एक्सप्रेस–वे के लिए निर्माणकर्ता के चयन को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। एक्सप्रेस–वे का निर्माण तीन वर्ष से भी कम समय में कराया जायेगा।

लखनऊ से निकलेगा लिंक एक्सप्रेस–वे

पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे में लखनऊ के पास से ही इलाहाबाद के लिए लिंक एक्सप्रेस–वे निकाला जायेगा। इसके साथ ही गोरखपुर के लिए भी एक लिंक एक्सप्रेस–वे फैजाबाद से निकाला जाएगा।

लोकतंत्र सेनानियों को मिलेगी 20 हजार रूपये सम्मान राशि

आपातकाल के दौरान मीसा, डीआईआर में बंद प्रदेश के राजनीतिक बंदियों को वर्तमान में सरकार की ओर से 15000 रूपये प्रतिमाह की सम्मान राशि मिल रही है। अब 5000 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए कैबिनेट ने सम्मान राशि 20 हजार रूपये प्रतिमाह देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यह बढ़ोतरी एक जुलाई से लागू होगी।

परिवहन निगम कर्मियों को एक अप्रैल से पुनरीक्षित सातवें वेतन का भुगतान

जीआईसी व जीजीआईसी में कंप्यूटर प्रवक्ता के 130 पद मंजूर

34वीं वाहिनी पीएसी में सेनानायक भवन मल्टीपरपज हॉल को मंजूरी

गाजियाबाद में समेकित विशेष विद्यालय के अधूरे काम जल्द होंगे पूरे

गोरखपुर का पीपीगंज ब्लॉक खत्म, भरूहिया नया बनेगा

सिंघाड़ा से विकास सेस समाप्त

कामर्शियल वाहनों की परमिट फीस में बढ़ोत्तरी

प्रदेश सरकार ने कामर्शियल वाहनों की परमिट फीस में अलग–अलग वाहनों के लिए 20 से लेकर 100 फीसदी तक बढ़ोत्तरी की है। फीस बढ़ोतरी से परिवहन विभाग को करीब 14 करोड़ रूपये सालाना अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।

27438 करोड़ लागत से लखनऊ में बनेंगे तीन फ्लाई ओवर

राज्य योजना के अंतर्गत लखनऊ में तीन फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तीनों फ्लाई ओवर के निर्माण में लगभग 27438 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

विधान सभा लखनऊ पश्चिम में चरक चौराहा–हैदरगंज तिराहा, चरक क्रासिंग से विक्रम काटन मिल तक दो लेन फ्लाई ओवर बनेगा, जबकि विधान सभा लखनऊ पश्चिम के ही तुलसीदास मार्ग पर हैदरगंज तिराहा से मीना बेकरी से पूर्व तक दो लेन फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाएगा। विधान सभा लखनऊ उत्तर में गुरु गोविन्द सिंह मार्ग पर हुसैनगंज चौराहा बासमंडी चौराहा होते हुए नाका हिंडोला डीएवी कालेज के मध्य तीन लेन फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाएगा। इस पर लगभ 12380 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है जबकि लखनऊ पश्चिम के दोनो फ्लाई ओवर के निर्माण में लगभग 15058 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

तीनों फ्लाई ओवर के बन जाने से लखनऊ शहर के निवासियों को आवागमन में सुविधा के साथ–साथ रोजमर्रा लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी